Dr.Raman Kumar Thakur

Assistant professor (Guest) Deptt.Of Economics, D.B.College, Jaynagar, Madhubani.

Class:- B.A.part-2(Hons.)Date:-29-10-2020.Lecture n.-31.

Topic:- "भारत में कृषि-विकास एवं ग्रामीण ऋणग्रस्तता" (Agricultural Development and Rural Indebtadness in India)

:- भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय नियोजन में कृषि विकास को आधारभूत दृष्टिकोण के रूप में स्वीकार किया गया। देश की तत्कालीन खाद समस्या को ध्यान में रखकर ही प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार अवसर के दृष्टिकोण से कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 56% भाग कृषि कार्य में संलग्न है तथा कृषि क्षेत्र से सकल घरेलू उत्पाद का

लगभग 14.6% प्राप्त होता है वानकी और मत्स्यकी का हिस्सा क्रमशः 1.5% तथा 8.8% था ।

- कृषि विकास का मूल्यांकन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है:- कृषि क्षेत्र की औसत विकास दर 2007-08 में 5.8% , 2008-09 में 0.7%,2009-10 में 0.4%अनुमानित की गई है ।

* कृषि उत्पादन तथा विकास वर्ष 2007-08 में देश में खाद्यान्न उत्पादन 230.78 मिलियन टन अनुमानित किया गया था, वर्ष 2008-09 के दौरान कृषि उत्पादन का अनुमान 234.47 मि.टन लगाया गया था जबकि लक्ष्य 233 मिलियन टन था । वर्ष 2009-10 के लिए अंतिम अनुमान कुल खाद्यान्न 218.11 मि. टन अनुमानित किया गया था।2010-11 के दूसरे अग्रिम अनुमानों में खाद्यान्न उत्पादन का 232.07 मिलियन टन का अनुमान लगाया गया।

* भारतीय कृषि की विशेषताएं1). जीविकोपार्जन का साधन 2).उपभोग का मूल आधार . 3).खाद्यान्न फसलों की मुख्यता 4).निम्न कृषि उत्पादकता।5),भारतीय कृषि श्रम प्रधान है.6). प्रकृति पर निर्भरता.7) परंपरागत खेती,8). पूरे वर्ष रोजगार का अभाव, 9).भारतीय कृषि में यंत्रीकरण का अभाव.10). किसानों का अशिक्षित होना.